न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, उम्मेद सिंह रतनू, आर.ए.एस.

अपील संख्या 145/2025 निर्णय दिनांकः– 18-3-26
(जीसीएमएस संख्या 2025/280)

1. किसनाराम पुत्र हेमाराम जाति जाट निवासी पलाना तहसील व जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, पूगल।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्ध आज्ञा दिनांक 18–10–2002
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर

उपस्थितिः–

1. श्री विजय भादाणी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट् ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, छत्तरगढ़, मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 18–10–2002 जिसके द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विकय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् द्वारा तहसील पूगल में वर्ष 1988 में भूमि के आवंटन हेतु तमाम सबूतों के साथ आवंटन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था। अपीलांट् द्वारा अपने आवंटन प्रार्थना पत्र के साथ तमाम सबूत यथा भूमि काश्तकारी पेशा व शपथ पत्र आदि प्रस्तुत किये गये थे। अदालत मातहत द्वारा आवंटन मात्र इस आधार पर खारिज किया गया है कि उपनिवेशन तहसील पूगल में बारानी भूमि में आवंटन हेतु राज्या देश क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द कर दिया गया है।

इस संबंध में अपीलांट् को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। यदि जारी किया भी गया है तो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील विधिवत नहीं कराई गई है। अपीलांट् ने जब अपना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तब कोई तारीख पेशी नहीं बताई गई थी। अदालत मातहत द्वारा बारानी भूमि आवंटन बन्द होने के कारण आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जबकि राज्य सरकार के राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के द्वारा दिनांक 13–03–1991 द्वारा बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को हटा दिया गया है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत को चाहिए था कि अपीलांट् के प्रार्थना पत्र को खारिज करने के स्थान पर आवंटन हेतु अथवा उक्त रोक को हटाये जाने तक लम्बित रखना चाहिए था। अदालत मातहत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर परिपत्र की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् के आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। जो किसी भी तरह से विधि सम्मत नहीं है।

अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर मनमाने ढंग से पारित किया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व सुनवाई व सबूत का कोई अवसर अदालत मातहत ने प्रदान नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट्स को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उन्होंने

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियाद पर बताया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा क्षेत्राधिकार से बाहर है। जिसमें मियाद अधिनियम बाधक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियाद घोषित की जावे। अपने कथनों के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट द्वारा आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया गया।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने अपील काफी विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मियाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किया है। अपीलांट का आवंटन सबूतों के अभाव में खारिज किया जा चुका है। अब अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रकरण में गुणावगुण पर निर्धारण से पूर्व मियाद के बिन्दु को अभिनिर्धारित किया जाना उचित पाते है। जहाँ तक मियांद का प्रश्न ह, अपील मियाद अवधि की समाप्ति के पश्चात पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके खण्डन में रेस्पोडेन्ट द्वारा कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुनवाई एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। न्यायिक दृष्टांत आरएलडब्ल्यू 2005 (2) आरजे पेज 596 में भी अभिधारित किया है कि **"Period of limitation does not run against non-petitioner being ex-parte order."** अतः प्रकरण का निस्तारण मियाद की बजाय गुणावगुणप पर किया जाना श्रेयस्कर है। अतः न्यायहित में विलम्ब कंडोन कर अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

प्रकरण में जहाँ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट् ने भूमिहीन बारानी आवंटन के तहत आवंटन हेतु अदालत मातहत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत **करते** हुए आवेदन पत्र के साथ तमाम सबूत भी प्रस्तुत किये

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

गये। अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रार्थना पत्र उपनिवेशन तहसील पूगल में राज्यादेश क्रमांक एफ –3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 से इगानप क्षेत्र में बारानी भूमि का आवंटन बन्द करने के आधार पर अपीलांट के आवंटन प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। हमने अदालत मातहत की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलांट् द्वारा बारानी भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र राज्यादेश क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के अनुसरण में बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप खारिज किया गया है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर

इस संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा दौराने बहस राज्य सरकार राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 की प्रति प्रस्तुत की गई। जिसके द्वारा दिनांक 13–03–1991 को इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतद् द्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है, की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए आवंटन की कार्यवाही करने का कथन किया गया। इस संबंध में हमारा अभिमत है कि प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा अपनी अधिसूचना क्रमांक एफ–3 (25) उपनि/91, जयपुर दिनांक 13–03–1991 के माध्यम से बारानी भूमि के आवंटन पर रोक लगाई थी ना की उक्त अधिसूचना के माध्यम से बारानी भूमि आवंटन बन्द किया गया था। अदालत मातहत द्वारा स्वेच्छाधारी तरीके से राज्य सरकार की अधिसूचना की गलत व्याख्या करते हुए अपीलांट् का आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट् को किसी प्रकार की सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत परिपत्र राजस्व (उपनिवेशन) विभाग के आदेश क्रमांक प. 3 (25) उप/1991 दिनांक 18–06–2008 के माध्यम से दिनांक 13–03–1991 द्वारा इगानप (द्वितीय चरण) उपनिवेशन क्षेत्र में बारानी भूमि के आवंटन पर लगाई गई रोक को एतदद्वारा तुरन्त प्रभाव से हटाया जा चुका है। चूंकि अदालत मातहत द्वारा राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 13–03–1991 की गलत व्याख्या करते हुए आवंटन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् उक्त परिपत्र के अनुसरण में राहत प्राप्त करने का अधिकारी है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पूगल को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन परिपत्रों/नियमों के अनुसरण में अपीलांट् की आज दिनांक की पात्रता की जॉच करते हुए, पात्रता सही पाये जाने पर अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट् के प्रार्थना पत्र पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 18-3-26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर